



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2015/वैशाख 24, 1937

No. 127]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2015/VAISAKHA 24, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2015

फा.सं. 2(14)/2014 – ईजी-II.—विषय: सरकारी अनुप्रयोगों के स्रोत कोड खोल कर सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास पर नीति

क्र.सं.	डाटा तत्व	मान/मूल्य
1.	शीर्षक	सरकारी अनुप्रयोगों के स्रोत कोड खोल कर सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास पर नीति।
2.	दस्तावेज़ संस्करण, निर्माण तिथि	संस्करण 1.0
3.	प्रकाशक	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई)
4.	प्रकाशन की तिथि	अधिसूचना की तारीख
5.	मानक दस्तावेज़ का प्रकार (नीतिगत/तकनीकी विनिर्देश/सर्वोत्तम पद्धतियां/ दिशानिर्देश/प्रक्रियाएं)	नीति
6.	निर्माता (ऐसा एक निकाय जो प्राथमिक रूप से संसाधन बनाने के लिए जिम्मेदार है)	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई)

क्र.सं.	डाटा तत्व	मान/मूल्य
7.	योगदानकर्ता (ऐसा एक निकाय जो संसाधनों में योगदान करने के लिए जिम्मेदार है)	डीईआईटीवाई, भारत सरकार, झारखंड आईटी विभाग और एनआईसी, झारखंड राज्य यूनिट, रांची
8.	संक्षिप्त विवरण	<p>एक खुला स्रोत विकास मॉडल अपनाकर ई-शासन अनुप्रयोग विकास तथा शीघ्रता से रोल आउट/कार्यान्वयन की गति को बढ़ाना ही इस नीति का मूल उद्देश्य है। भारत सरकार मौजूदा विकसित अनुप्रयोगों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार स्रोत कोड खोलकर सफल, स्केलेबल एवं उच्च गुणवत्तायुक्त ई-शासन अनुप्रयोगों को सहयोगात्मक तरीके से विकसित करना चाहती है। यह रचनात्मकता - विभागों/संस्थानों और निजी संगठनों, नागरिकों और विकासकर्ताओं के बीच सहयोगात्मक विकास को बढ़ावा देकर नवाचारी ई-शासन अनुप्रयोग और समाधान तैयार करने के लिए अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर नए अनुप्रयोग विकसित करना चाहती है।</p> <p>जनता के लिए अनुप्रयोग स्रोत कोड के इस्तेमाल और उन्हें जारी करने सहित ई-शासन अनुप्रयोग स्रोत की खुली पहल से लागत और विकास में लगने वाले समय को कम किया जा सकता है तथा उन्नत पारदर्शिता और बड़े पैमाने पर जन समीक्षा के माध्यम से समग्र गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार किया जा सकता है।</p>
9.	लक्षित स्रोत (जो दस्तावेज का संदर्भ लेंगे/उपयोग करेंगे)	केंद्रीय और राज्य सरकार के सभी विभाग और अन्य सरकारी संस्थान, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती हैं, सरकारी और निजी संगठन, जिन्हें सरकारी विभागों द्वारा सेवा में लगाया गया है, अन्य अनुप्रयोग विकासकर्ता, ओईएम, लेखापरीक्षा संस्थानों आदि
10.	अनुमोदित नीति का स्वामी	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई)
11.	कवरेज स्थान	भारत
12.	भाषा (बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना है)	अंग्रेजी (जिसका बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना है)
13.	कॉपीराइट	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई)
14.	स्रोत (उस संसाधन का संदर्भ जिससे वर्तमान संसाधन निकाला गया है)	शून्य
15.	संबंध (डीईआईटीवाई द्वारा अधिसूचित अन्य ई-शासन मानकों के साथ संबंध)	लागू नहीं

प्रस्तावना

भारत सरकार (जीओआई) का उद्देश्य विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों/उपकरणों/उत्पादों के स्रोत कोड को यथाउपयुक्त समझे जाने पर और जिनके बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) विभिन्न सरकारी संस्थाओं के पास हैं, उनको सार्वजनिक करना है। सरकार ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि इससे सहयोगात्मक विकास के जरिए पुनः उपयोग, तेजी से वितरण, उत्पाद मानकीकरण, नवाचार, गुणवत्ता सुधार और लागत की बचत का उद्देश्य पूरा होगा।

प्रभावी तिथि

यह नीति अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

पृष्ठभूमि

केंद्र और राज्यों, दोनों स्तरों पर सरकारी विभाग और संस्थानों सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के विकास में लगे हैं और इस तरह के ज्यादातर अनुप्रयोग उनके परिसरों में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। हालांकि, ऐसा हो सकता है कि कार्यों की पुनरावृत्ति हो रही हो। कई अनुप्रयोगों अन्य विभागों में पहले से ही विद्यमान हैं और चल रहे अनुप्रयोग का पुनः उपयोग किए बिना फिर से उन्हें विकसित किया जा रहा है। एक सामान्य सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास मंच के अभाव में, सरकारी विभागों द्वारा विकसित व्यक्तिगत अनुप्रयोग एक जैसी अनुप्रयोग प्रकार्यात्मकता के लिए समान कोड के साथ समाप्त हो सकते हैं, जो अन्यत्र कहीं पहले से ही उपलब्ध है। स्रोत कोडों को साझा करने के लिए सामान्य मंच के अभाव में कोडों की जांच नहीं हो पाती है, इस प्रकार उनमें आगे सुधार के अवसर समाप्त हो जाते हैं। इन अकुशल प्रथाओं के फलस्वरूप, जो समय, प्रयास और जनता के पैसे की बर्बादी हो सकती है, जिसका वैकल्पिक रूप से और अधिक उत्पादक उपयोग किया जा सकता था।

सैकड़ों कस्टम अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों और संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शहरी स्थानीय निकायों में चल रहे हैं। एक एकीकृत मंच पर इन अनुप्रयोगों के स्रोत कोड की होस्टिंग, जहां सरकारी विभागों/संस्थानों और आम जनता (आवश्यक पहुँच नियंत्रण के साथ) के द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है, के फलस्वरूप, बेहतर सहयोगी तरीके से बहुत तेजी से अनुप्रयोग विकास किया जा सकेगा।

उद्देश्य

"सरकारी अनुप्रयोगों के स्रोत कोड खोल कर सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास पर नीति" सहयोग और पुनरावृत्ति से बचने के लिए उनके पुनः उपयोग, मानकीकरण, नवाचार, गुणवत्ता सुधार और लागत में बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

प्रयोज्यता

यह नीति ऐसे सभी सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों/उपकरणों/उत्पादों के लिए लागू है, जिनके आईपीआर किसी भी सरकारी संस्था के पास हैं और जो संबंधित सरकारी निकाय अपने स्रोत कोड को सार्वजनिक करना चाहते हैं, के लिए लागू है। यह नीति इस नीति के प्रभावी तिथि के बाद शुरू किए गए सभी सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग विकास कार्यों के लिए लागू होगी। यह नीति सभी अनुप्रयोग विकास प्रयासों के लिए लागू होगी, चाहे वे इनहाउस अथवा किसी सॉफ्टवेयर विकास संस्था के माध्यम से किए जाएंगे। इस नीति के प्रभावी तिथि से पूर्व विकसित किए गए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों/संघटकों पर इस नीति को लागू करना अपेक्षित है परंतु अनिवार्य नहीं है। सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग/संघटक/अनुप्रयोग विकास सेवाओं के लिए किसी भी खरीद संबंधी कार्रवाई के लिए इस नीति और इसके निहितार्थ पर अपेक्षित विचार किया जाना चाहिए।

यह नीति राष्ट्रीय सामरिक महत्व की परियोजनाओं/संगठनों के लिए उपयोग अथवा कार्यान्वयन के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों/उपकरणों/उत्पादों और उन परियोजनाओं/अनुप्रयोगों के लिए लागू नहीं है, जिनके सुरक्षा निहितार्थ हो सकते हैं। यह नीति कॉमर्शियल ऑफ द शेल्फ (सीओटीएस) सॉफ्टवेयर पर लागू नहीं होती है।

नीतिगत विवरण

भारत सरकार सरकारी अनुप्रयोगों के स्रोत कोड खोल कर सहयोगी अनुप्रयोग विकास की दिशा में एक समान नीति अपनाएगी जिससे कि अन्य सरकारी डोमेनों के लिए सॉफ्टवेयर विकास, पुनः उपयोग और तेजी से रोल आउट का एक नया और बेहतर तरीका सुनिश्चित किया जा सके।

1. सरकार के पास किसी भी सरकारी संस्था द्वारा या सरकार द्वारा वित्त पोषित निजी संस्थानों द्वारा विकसित किसी भी अनुप्रयोग के लिए सॉफ्टवेयर स्रोत कोड के कस्टमाइज़ - निर्मित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

2. यदि यह एक सीओटीएस उत्पाद है, तो सरकार को सीओटीएस उत्पाद पर किसी भी कस्टमाइजेशन कोड पर पूर्ण अधिकार होगा बशर्ते कि इसकी खरीद सरकार द्वारा की जा रही हो। सरकार को अगर जरूरी है तो किसी भी अन्य सरकारी विभाग या संस्था के लिए कस्टमाइजेशन कोड का पुनः उपयोग करने का अधिकार होगा। 'सीओटीएस पर कस्टमाइजेशन' में जो घटक/कोड/मॉड्यूल शामिल होते हैं, को सरकार और कस्टमाइजेशन कर रही संस्था के बीच अनुबंध में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
3. यदि कोई संस्था स्रोत कोड कस्टमाइज करती है अथवा किसी विशेष सरकारी कस्टम-निर्मित अनुप्रयोग या सीओटीएस पर कस्टमाइजेशन कोड के लिए कोई भी मॉड्यूल एड करती है या प्लग-इन करती है, तो सरकार के पास इस प्रकार एड किए गए मॉड्यूल, प्लग-इन या कस्टमाइजेशन कोड के स्रोत कोड पर पूरा अधिकार सुरक्षित होगा।
4. सरकार में पहले से सफलतापूर्वक चल रहे अनुप्रयोग के मामले में, जिसका कोड खोला जाता है और जिसका आईपी सरकार के स्वामित्व में है, तो उसे किसी भी अन्य सरकारी विभाग / संस्था के लिए एक वाणिज्यिक आधार पर निजी संस्थानों द्वारा कार्यान्वित करने की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में अनुप्रयोग स्रोत कोड के लिए कोड में परिवर्तन की अनुमति है, लेकिन सरकार के पास संशोधित अनुप्रयोग के स्रोत कोड के लिए पूरे अधिकार सुरक्षित होंगे।
5. विकसित किए जाने की सभी सरकारी अनुप्रयोग स्रोत कोडों को सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास मंच पर साझा किया जाएगा। खुला स्रोत विकास के लिए एक प्रभावी और विश्वसनीय मंच प्रदान करने के लिए, यह सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास मंच के पास उचित नियंत्रण तंत्र, संस्करण प्रबंधन और आवश्यक कार्यक्षमता, सुरक्षा, प्रदर्शन, डिजाइन, कोडिंग प्रथाओं और अन्य आवश्यक विशेषताओं के सत्यापन/वैधीकरण संबंधी नीतियों पर नियंत्रण होगा।
6. किसी भी सरकारी संस्था द्वारा विकास या खरीद के लिए किसी भी नए सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन करते समय, सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास मंच में पहले से ही उपलब्ध सॉफ्टवेयर को वरीयता दी जानी चाहिए।
7. नीति के अंतर्गत सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास मंच पर अपने अनुप्रयोग स्रोत कोड खोलने के लिए पहले से ही विकसित मोनोलिथिक अनुप्रयोगों को अधिदेशित नहीं किया जाता है, तथापि यह सिफारिश की जाती है कि भारत सरकार द्वारा तैयार किए जाने वाले दिशा-निर्देशों अपेक्षित गुणवत्ता और सुरक्षा जांच के पश्चात सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास मंच में इंस्टालेशन लिपि, इंस्टालेशन दस्तावेज़, डेटाबेस स्कीम और किसी भी अन्य दस्तावेजों के साथ अनुप्रयोग स्रोत कोड और वस्तु कोड साझा किया जाएगा। इन दिशा-निर्देशों से सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास मंच के लिए शासन ढांचे, संचालन प्रक्रियाओं, अनुप्रयोग परिपक्वता मूल्यांकन मॉडल, अनुप्रयोग स्थिरता मॉडल, लाइसेंस नीति आदि की समस्याओं का समाधान होगा।
8. सरकारी परियोजनाओं की भावी खरीद प्रक्रियाओं में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकार को कस्टम-निर्मित अनुप्रयोग विकास के स्रोत कोड और असीमित अधिकार प्राप्त हों। सीओटीएस उत्पाद के मामले में, संविदा खंड में **कॉमर्शियल ऑफ द शेल्फ** उत्पाद पर कस्टमाइजेशन कोड के लिए पूरे अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। अधिकारों में सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में कहीं भी कस्टमाइजेशन कोड के पुनः उपयोग को शामिल किया जाना चाहिए।
9. नीति या तो सरकारी अनुप्रयोगों के विकास अथवा कार्यान्वयन और समर्थन में किसी भी निजी/सरकारी निकाय के वाणिज्यिक हितों को सीमित/प्रतिबंधित नहीं करती है। वाणिज्यिक शर्तों का निर्धारण संबंधित सरकारी विभागों और संस्थानों तथा समाधान प्रदाताओं के बीच आपसी तौर पर सहमति से किया जा सकता है। नीति में केवल इस बात का जिक्र किया गया है कि विकास के सहयोगी पहल के जरिए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के त्वरित कार्यान्वयन और मूल्यवर्धन के व्यापक हित के लिए अनुप्रयोग स्रोत कोड खोला जाए।
10. यदि अन्य लोगों द्वारा पुनः इस्तेमाल के लिए अनुप्रयोग/घटक डाउनलोड किया जाता है, तो इस नीति के अंतर्गत स्रोत ओपन सरकारी परियोजनाओं के लिए योगदानकर्ताओं द्वारा समर्थन प्रदान करने पर कोई बाध्यता लागू नहीं की जाती है। यह सिफारिश की जाती है कि योगदानकर्ताओं को कोड में सुधार करने में या इसके फिर से उपयोग के दौरान दूसरों की मदद करनी चाहिए।

11. जिम्मेदारियां

#	पणधारक	भूमिका	आवश्यक कार्रवाई
1.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सूत्रधार	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना के लिए समग्र मार्गदर्शन एवं निधियन सरकारी अनुप्रयोगों के स्रोत कोड खोल कर सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास पर नीति जारी करना दिशा-निर्देश जारी करना
2.	एनआईसी (सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रभाग)	प्लेटफार्म के लिए कार्यान्वयन संस्था	<ul style="list-style-type: none"> जागरूकता एवं संवर्धन अनुप्रयोग मालिकों की ऑनबोर्डिंग सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास मंच की स्थापना, स्वामित्व और परिचालन प्रबंधन।
3.	मंत्रालय/विभाग/एनआईसी/ सी-डैक आदि	अनुप्रयोग मालिक/विकासकर्ता	<ul style="list-style-type: none"> "सरकारी अनुप्रयोगों के स्रोत कोड खोल कर सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास पर नीति" का अनुपालन नीति के अनुसार मौजूदा स्थिर अनुप्रयोगों के स्रोत कोड रिलीज करना अनुप्रयोग विकास के लिए सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास मंच का उपयोग करना सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास मंच पर सूचीबद्ध/प्रकाशित परियोजनाओं के लिए योगदान
4.	मंत्रालय/विभाग	अनुप्रयोग प्राप्तकर्ता	<ul style="list-style-type: none"> सरकारी सहयोगी अनुप्रयोग विकास मंच पर प्रकाशित अनुप्रयोगों को अपनाना अनुप्रयोग संशोधनों/ संवर्धन के लिए योगदान देना नीति का अनुपालन करना
5.	मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर विकासकर्ता/शैक्षणिक संस्थान	योगदानकर्ता	<ul style="list-style-type: none"> मंच के उपयोग और विस्तार में सक्रिय भागीदारी। प्रकाशित अनुप्रयोगों का परीक्षण और ज्ञात सुभेद्यताओं का प्रकाशन करना

नीति की समीक्षा

सरकार के पास आवश्यक होने पर इस नीति को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

संपर्क बिंदु

इस नीति से संबंधित सभी प्रश्न या टिप्पणियां संयुक्त सचिव (ई-गवर्नेंस), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, (डीईआईटीवाई) इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 को jsegov@deity.gov.in, पर निर्देशित की जाएंगी।

आर. एस. शर्मा, सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2015

F. No. 2(14)/2014 – EG-II.—Policy On Collaborative Application Development by Opening the Source Code of Government Applications

S. No.	Data elements	Values
1.	Title	Policy on Collaborative Application Development by Opening the Source Code of Applications.
2.	Document Version, Creation date	Version 1.0
3.	Publisher	Ministry of Communication and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (DeitY)
4.	Date of Publishing	Date of Notification
5.	Type of Standard Document (Policy/Technical Specification/Best Practice/Guideline/Process)	Policy
6.	Creator (An entity primarily responsible for making the resource)	Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (DeitY)
7.	Contributor (An entity responsible for making contributions to the resource)	DeitY, Govt of India, Jharkhand IT department & NIC Jharkhand State Unit, Ranchi
8.	Brief Description	<p>The policy intends to increase the pace of eGovernance application development and rapid roll out/implementation by adopting an open-source development model. The Government of India wants to promote re-use of existing developed applications. By opening the source code, the Govt. wants successful, scalable, high quality eGov applications to be developed in a collaborative manner. It also wants new applications to be developed to encourage creativity - both inside and outside the Government by encouraging collaborative development between Govt. departments/agencies and private organizations, citizens and developers to create innovative eGov applications and solutions.</p> <p>eGov application source open approach including the use and release of application source code to public can reduce costs and development time and improve the overall quality and security through increased transparency and mass peer review.</p>
9.	Target Audience (Who would be referring / using the document)	All Central and State Government Departments, and other Government Agencies providing public services electronically, Government & private organizations engaged by Government departments, other application developers, OEMs, Audit Agencies etc
10.	Owner of approved Policy	Ministry of Communication and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (DeitY)
11.	Coverage Spatial	India
12.	Language (To be translated in other Indian languages later)	English (To be translated in other Indian languages later)

13.	Copyrights	Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (DeitY)
14.	Source (Reference to the resource from which present resource is derived)	NIL
15.	Relation (Relation with other e-Governance standards notified by DeitY)	N/A

Preamble

The Government of India (GOI) aims to make public the source code of various software applications/components/products as it may consider suitable and whose Intellectual Property Rights (IPR) are held by various Government entities. It is intended that this will serve the purpose of reuse, faster delivery, product standardization, innovation, quality improvement and cost saving through collaborative development.

Effective date

This policy comes in force from the date of its publication.

Background

Government Departments and Agencies both at the centre and states are engaged in developing software applications and most such applications are running successfully in their own premises. However, there may be repetitive work going on. Many applications are being re-developed from scratch without reusing the already existing and running applications in other Departments. In the absence of a common Collaborative Application Development Platform, individual applications developed by Government Departments may end up with the same code being rewritten for similar application functionality, which is already available elsewhere. Lack of sharing of the source code prevents the code from scrutiny, thus denying the opportunity for further improvements. These inefficient practices may lead to wastage of time, efforts and public money, which could have been put to more productive use alternatively.

Several hundreds of custom application software are running across Central/ State Government Departments and Agencies, PSUs and urban local bodies. Hosting of the source code of these applications on a single unified platform which can be accessed by Government Departments/Agencies and the general public (with necessary access controls) would result in much faster application development in a better collaborative manner.

Objectives

The “Policy on Collaborative Application Development by Opening the Source Code of Government Applications” is designed with the objective of promoting reuse, standardization, innovation, quality improvement and cost savings through collaboration and avoidance of duplication.

Applicability

This policy is applicable to all software applications/ components/ products whose IPR are held by any Government entity and which the concerned Government entity considers suitable for making the source code public. This policy will be in force for all software application development exercises initiated after the effective date of this policy. This policy will apply to all software application development efforts, whether in-house or through a software development agency. Applicability of this policy on software applications/components developed prior to the effective date of this policy is desirable but not mandatory. Any procurement exercise for software application/component/application development services should give due consideration to this policy and the intent behind it.

This policy is not applicable on software applications/components/products utilized or implemented for projects/organizations of national strategic importance and for those projects/applications that may have security implications. The policy does not apply to Commercial off the Shelf (COTS) software.

Policy Statement

Government of India shall adopt uniform policy towards collaborative application development by opening the source code of Government applications to ensure a new and agile way of developing software, reuse and rapid roll out to other Government domains.

1. The Government will have full rights to custom-built software source code for any application developed by any Government agency or by private agencies funded by the Government.
2. If it is a COTS product, then the Government will have full rights on any customization code on the COTS product if it is procured by the Government. The Government shall have the right to reuse the customization code for any other Govt. department or entity if required. What components/code/modules constitute 'customizations on COTS' will be specified in the contract between the Government and the agency doing the customization.
3. If any agency customizes the source code or adds any modules or plug-ins to a particular Government custom-built application or customization code on COTS, the Government reserves the full rights of the source code of the add on modules, plug-ins or customization code.
4. In case an already successfully running application in the Government, whose code is opened and whose IP is owned by Government, needs to be rolled out by private agencies on a commercial basis for any other Government Department/Agency, code changes to the application source code is permissible, but Government reserves full rights to the source code of the modified application.
5. All Government application source code to be developed will be shared on the Collaborative Application Development Platform. To provide an effective and reliable platform for open source development, this Collaborative Application Development Platform shall have proper control mechanisms, version management and policies on verification/validation of the codes w.r.t required functionality, security, performance, design, coding practices and other necessary attributes.
6. While evaluating any new software for development or purchase by any Government entity, preference should be given to software already available in the Collaborative Application Development Platform.
7. The policy does not mandate already developed monolithic applications to open their application source code on the Collaborative Application Development Platform, However, it is recommended that the application source code and the object code with installation script, installation document, database schema and any other documents be shared in the Collaborative Application Development Platform after due quality and security checks will be laid in the guidelines by Government of India. These guidelines would also address governance framework, operational processes, application maturity assessment models, application sustainability models, licensing policy etc. for the Collaborative Application Development platform.
8. The future procurement processes of the Government projects should ensure that the Government receives the **source code and unlimited rights** of custom-built application development. In case of COTS product, the contract clauses should secure full rights to customisation code developed on the **Commercial Off The Shelf** product. The rights should cover reuse of customization code anywhere else in the Government or public sector.
9. The policy does not restrict/prohibit any private/Government entity's commercial interest either in development or implementation and support of Government applications. The commercial terms can be worked out between the concerned Government Departments and Agencies and solution providers on mutually agreed terms. The policy only that the application source code be opened for larger interest of rapid roll out and value addition to the application software through collaborative approach of development.
10. The policy does not impose any obligation on contributors to the source open Government projects to provide support if the application/component is downloaded for reuse by others. It is recommended that contributors should help others in improving the code or during its re-use, but this is not binding.

Responsibilities

#	Stakeholders	Role	Actions Required
1.	Department of Electronics & Information Technology Ministry of Communications and Information Technology	Facilitator	<ul style="list-style-type: none"> Overall Guidance & Funding for the project Issuing Policy on Collaborative Application Development by Opening the Source Code of Government Applications Issue of Guidelines
2.	NIC (System Software Division)	Implementation Agency for Platform	<ul style="list-style-type: none"> Awareness & Promotion Application Owner Onboarding

#	Stakeholders	Role	Actions Required
			<ul style="list-style-type: none"> Setting up, ownership and operational management of Collaborative Application Development Platform.
3.	Ministries/ Departments/ NIC/ CDAC etc.	Application Owners/ developers	<ul style="list-style-type: none"> Compliance to “Policy on Collaborative Application Development by Opening the Source Code of Government Applications” Release of source code of existing stable applications as per policy Usage of Collaborative Application Development Platform for application development Contribution to projects listed/published on Collaborative Application Development Platform
4.	Ministries/ Departments	Application Seekers	<ul style="list-style-type: none"> Adoption of applications published on Government collaborative Application development platform Contributing to application modifications/enhancements Compliance with the Policy
5.	Recognized Software Developers/ Academic institutions	Contributors	<ul style="list-style-type: none"> Active involvement in platform usage and enhancement. Testing of published application and publishing known vulnerabilities.

Review of the Policy

The Government shall have the right to revise the Policy as and when required.

Point of Contact

All queries or comments related to this Policy shall be directed to JS (e-Governance), DeitY (jsegov@deity.gov.in), Department of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003 .

R.S. SHARMA, Secy.